उद्योगों को रियायतों की खुराक, विदेशी निवेश लुभाने पर जोर

राब्यू, लखनऊ: सरकार ने बजट में छोटे-बड़े उद्योगों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा खोला है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी खास तौर पर रियायतें दी गई हैं। अवस्थापना और औद्योगिक विकास, एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग व हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4957.76 करोड़ की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट के विस्तार एवं भूमि अर्जन के लिए बजट में 2400 करोड़ का प्रविधान किया है।

महाकुंभ-2025 से पूर्व गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को पूर्ण करने के लिए 2057.76 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। उप्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फार्च्यून 500 कंपनी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के जरिये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी 400 करोड़ रखा गया है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य: सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के तहत लखनऊ-हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्वीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव है।

अयोध्या में 'महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम' के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ रुपये का किया गया प्रविधान**
- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था**

किस क्षेत्र को कितना बजट

अवस्थापना और औद्योगिक विकास : 3,207.76 करोड़

एमएसएमई- 1000 करोड़

खादी एवं ग्रामोद्योग- 41 करोड़

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- 750 करोड़

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरने की कड़ी में अगले वित्तीय वर्ष भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) का आयोजन होगा। इसके लिए 20 करोड़।
- उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बजट में 67.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट में एक लाख रुपये की प्रतीकात्मक व्यवस्था।
- विश्व में अगले सात वर्षों में कहीं भी आयोजित होने वाले 'मोटो जीपी रेस' के आयोजन स्थलों में प्रदेश सरकार और इन्वेस्ट यूपी के 'लोगो' को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए बजट में दस करोड़ रुपये का प्रविधान।
- राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ में नई आधुनिक प्रेस की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।